



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 1985/ माघ 16, 1906

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 1985/MAGHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सभ्यता की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सामर्थ्यपूर्ण सूचना सं० १३ आई टी सी (प एन)/११-९५

नई दिल्ली 5 फरवरी 1985

विषय — 1982-83 के डी एम 10 मिलियन 1983-84 के डी एम
25 मिलियन 1983-84 के डी एम 15 मिलियन और
1984-85 के लिए 60 मिलियन के पश्चिमी जर्मनी पंजीगत
माल क्रेडिट के अंतर्गत किए गए आयातों के लिए लागू
लाइसेंसिंग शर्तें।

मिसिल सं. आई ए सी/23(11)/84-85 — पश्चिमी जर्मनी
पंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत किए गए आयातों के मजाल में हेतु इस
मासिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई शर्तें एवं निबंधन सूचनाएं
अधिसूचित की जाती हैं।

प्रकाश चंद जैन, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

परिशिष्ट

1982-83 के डी एम 10 मिलियन 1983-84 के डी एम 25
मिलियन 1983-84 के डी एम 15 मिलियन और 1984-85 के लिए

डी एम 60 मिलियन के पश्चिमी जर्मनी पंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत
जागे किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू शर्तें।

1 (1) जिस समझौते में पंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित
आइटम का मूल्य 2 मिलियन डी एम के तुल्य रूप से अधिक होता है
[सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड 15 के अंतर्गत राजस्व (सीमा
शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर निश्चित
करके तुल्य रूप से] उसमें आश्रय के लिए पंजीगी के प्राधिकारियों
[नेटिडान्स टाइट पर वीडिफाऊ (कंप्यूटर)] की पूर्ण सहमति आवश्यक
है और यह सहमति भारतीय आयातक द्वारा अनुबंध 1 के प्रपत्र में दिए
गए परियोजना आदेशों के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त
की जाएगी। जब तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों में सहमति आर्थिक
कार्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों (मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात)
को नहीं भेज दी जाती है तब तक भारतीय आयातक को कोई भी
आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।

1 (2) लाइसेंस पर 1983-84 के लिए 25 मिलियन डी एम
पश्चिमी जर्मनी पंजीगत माल क्रेडिट अधिलेख अंकित किया जाएगा।
प्रथम और द्वितीय प्रत्यक्ष के लाइसेंस सबेन "एस/जी एन" होंगे। ये
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस की अंशित करने वाले
पत्र में भी दर्ज किए जाएंगे।

1 (3) बैंक खर्च जो सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं के अनिवार्य आयात लाइसेंस के प्रति विशिष्ट मुद्रा के किसी धन रेपण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेंट का कमीशन, यदि कोई होगा तो उसके भुगतान एजेंट को भारत में भारतीय रुपए में करने चाहिए ताकि ऐसा भुगतान लाइसेंस गत्य वा ही सा होगा और इसलिए लाइसेंस पर हो प्रसारित किया जाएगा।

1 (4) इस आयात लाइसेंस के अधीत अधिप्राप्त किए जाने वाले भाग और संबंधित सेवाएं बलित नैड या अन्य किसी देश मजिद अर्थात् गणतंत्र सभ से आयात किए जा सकते हैं। इसलिए विदेशी सभरक सविदा को पूर्ण करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो तीसरे देश से सामान आदि अधिप्राप्त करने के लिए स्यतन्त्र है।

1 (5) इस न्यूनतम और अधिकतम राशि जिसके लिए इन्वेंट्री के अंतर्गत एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह लगभग 30,000 डी एम और 5,000,000 डी एम के रूप में बराबर है लेकिन विनिर्दिष्ट सामान में, आर्थिक कार्य विभाग किन सभरक द्वारा अधिकतम सामान में 7,000,000 डी एम तक दोन दो जा सकते हैं (राजस्व) सामान शुल्क विभाग द्वारा अनिवार्यता मुद्रा विनिमय की दर पर गिन कर मुख्य (रुपया) मुद्रा विनिमय की दर पर मुख्य निर्यात आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में 78-आई टी सी (पा एन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के अनुसार आयात लाइसेंस में निरदिष्ट होना चाहिए।

1 (6) लेकिन आयात लाइसेंस लागत-सीमा भाग के आधार पर 24 महोनों या तीसरे पैरा 2(12) में यथा निरदिष्ट गंतव्यता की अन्तिम तिथि इनमें जा भी कम हो उन तब को प्रारम्भिक वैधता अवधि कायम इस शर्त से अर्थात् जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस को न्यूनतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि में 12 महोने होंगे।

1 (7) पक्के आदेश जिसका अर्थ है भारतीय लाइसेंस धारक द्वारा विदेशी सभरक को एक आदेश और विदेशी सभरक दांनो के द्वारा प्रिप्रिन्ट हस्ताक्षरित कय सविदा (आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महोनों की अवधि के भीतर हो अवधि निर्णीत हो जाने चाहिए) देखिए नीचे वा पैरा 1(9)। समुद्र पार सभरकों के भारतीय अधिकारियों को आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टि आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1 (8) यदि उपर्युक्त पैरा 1(7) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महोनों की समय सीमा के भीतर निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को आदेश देने की अवधि में वृद्धि मांगने हुए एक प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी सी आई एंड ई) को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी का जैसा भी मामला हो, इस बात का औचित्य और स्पष्टीकरण देने हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा गुणावृण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महोनों की और अवधि तक वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महोनों से अधिक होगी जानी है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निश्चयान्मक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी-1 अनुभाग) किन सभरक, तार्थ ब्याक, नई दिल्ली का भेजे जाएंगे जो ऐसी वृद्धि के प्रत्येक मामले का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और अपने निर्णय का लाइसेंस प्राधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिए भेजेंगे। केवल लाइसेंस प्राधिकारी वृद्धि या सभरक प्रदान करने वाले केवल ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही विदेशी मुद्रा की प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, मुख्य रूप से जमा करने की स्वतंत्रता आदि की सुविधा को अनुमति देते हैं।

1 (9) लाइसेंसधारी को अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्के आदेश की निर्धारित अवधि के भीतर पक्के आदेश का अन्तिम रूप दे दिया जाता है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता, उनमें लाइसेंसधारी को स्वयं आदेश देने की अवधि में उचित वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी/सम्बद्ध विभागीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक आप करेंगे कि लाइसेंसधारी 1 महोनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

1 (10) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं उनमें लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस के आदेश न दिए गए ऐसे शेष मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करें।

खण्ड 2 —यय सविदाएं निर्णीत करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेषताएं।

2(1) सविदा बायत विशेष रूप से उसी देश की मुद्रा में अभिव्यक्त होनी चाहिए जिसमें विदेशी सभरक रहता है। सविदा कीमत निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और किसी भी वृद्धि के लिए किया भी उपबन्ध का अनुमति नहीं होगा। यदि विदेशी सभरक के किसी सार्वजनिक एजेंट को कोई कमाशन चुकाया जाता है तो वह भारत में भारतीय रुपए में देय लागत गद के रूप में सविदा से अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इस पर विदेशी सभरक का विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि भारतीय एजेंट व ऐसे कमाशन से अलग प्रदर्शित होना चाहिए। आयात लाइसेंस के आन्तर पर जिस मूल्य तक अवधि आदेश दिए जा सकते हैं, उस मूल्य की विदेशी मूल्य का विदेशी मुद्रा में गणना करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमा मुख्य अतिविधियों 1962 के खण्ड-15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित की गई और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में 78-आई टी सी (पा एन)/74, दिनांक 6 जून 1974 के पैरा-2 में निरदिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकल्पित किया जाना चाहिए।

2 (2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में सभरण आदेश या तो लागत-सीमा-भाडा या लागत और भाडा आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामलों में आदेश केवल लागत और भाडा के आधार पर दिए जाने चाहिए।

3 (3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के अधीत कय सविदाएं विदेशी सभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक भारत सरकार का पृष्ठगत भाग समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार अपना पसंद के तिस भाग देश से आयात करने के लिए स्यतन्त्र है।

2 (4) अर्द्ध सविदा के लिए न्यूनतम मूल्य —वर्षों के एक आयात लाइसेंस के अन्तर्गत कय सविदा का सम्पूर्ण मूल्य 30,000 डी एम से कम (उन खर्च के मामले में जो पूर्णतया अर्जन, गणतंत्र सभ से किए गए हैं। या 30,000 डी.एम. के बराबर) उन मामलों में जहां अर्जन गणतंत्र सभ से भिन्न देशों से खर्च पूर्णतया या अंशतः किए गए हैं। होता चाहिए तो आयातक के लिए यह स्वतंत्रता है कि वह 30,000 डी एम से कम या 30,000 डी एम के बराबर अलग-अलग सविदाएं करे। किन्तु एक आयात लाइसेंस के अधिन उन कय सविदाओं के मामले में जिसका मूल्य डी.एम. 2 मिलियन के बराबर से अधिक नहीं होता तो यह नष्ट का कडिका 2(13) में निर्धारित शर्त के अधिन है।

2. (5-क) आयात लाइसेंस के अन्तर्गत त्रय संधिदाओं का भारत सरकार और क्रेडिटान्सटान्ट फार वॉर्रा फराइ (के एफ डब्ल्यू) (पश्चिमी जर्मनी विकास बैंक जिसके माध्यम से 25 मिलियन डी.एम. का पूंजीगत माल क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है और इसीलिए त्रय संधिदा में इस संबंध में एक विशेष धारा समाविष्ट करनी चाहिए।

(ख) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संधिदा जिसका मूल्य विभाग डी.एम. 2 मिलियन के बराबर रूपये या इससे कम हो (राजस्व "सीमा शुल्क") विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा (विनिमय की दर पर सगणित), के मामले में संधिदाओं के अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देने हुए बित्त मंत्रालय अधिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू के एक बार ही संधिदा दस्तावेज भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कार्यवाही कर सकता है जैसा कि के एफ डब्ल्यू द्वारा संधिदा अनुमोदन कर वांगई हो और यह कार्यवाही तब तक कर सकता है जब तक कि के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति नहीं करता के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति करेगा तो वह सही ढंग से आयातक को सूचित कर दी जाएगी।

(ग) आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संधिदा जिसका मूल्य डी.एम. 2 मिलियन के बराबर रूपये की धनराशि से अधिक हो (राजस्व "सीमा शुल्क") विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर सगणित), के मामले में पहले भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष रूप से भारतीय आयातक को भेजा जाएगा और जब तक यह ऐसा न हो तब तक संधिदाएं अनन्तम समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) के साथ त्रय संधिदा की तीन प्रतियां इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1 अनुभाग) कमरा नं. 69 मार्थ ब्लॉक को त्रय संधिदा के निर्यात होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी आवश्यक है कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलिया प्राप्त करने के बाद ही आवेश दिए गए हैं।

2. (6) जिस मामले में संधिदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक तदनुसार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करने चाहिए और संबंध बीमा कम्पनी से इस संबंध में एक बचनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो यह डी.एम. में सीधे के एफ डब्ल्यू को किया जाएगा।

(ड्यूटेस बन्डेस बैंक फैंकफर्ट/मेन की लेखा नं. 50409100)।

2. (7) जिस मामले में संधिदा लागत और बीमा भाग के आधार पर की गई है उसमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ करना चाहिए और तदनुसार बीमा विधित भाग्य रूप से चुकानी चाहिए। लेकिन आयातक का भारतीय बीमा कम्पनी से निगलिखित बचनपत्र प्राप्त करना चाहिए और उसकी संधिदा दस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (ईईसी-1 अनुभाग) को भेजनी चाहिए। —

"हम किसी भी उभ प्रतिस्थापन के लिए समुद्रपार संभरकों को विदेशी मुद्रा में धन परेषण करने के लिए आवश्यकता मान कर हानि या टूट-फूट के लिए हो सकती है।"

2. (8) शुद्ध संधिदाएं उपर्युक्त पैरा 2(2) के अनुसार या तो लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए चाहे भारतीय जहाज भी क्यों न उपयोग किए गए हों फिर भी विदेशी मुद्रा में भारी खर्चा चुकाने के लिए विदेशी संभरक को उत्तरदायी बनाना चाहिए। भाड़ा खर्चा किसी भी परिस्थिति में भारतीय रूप में चुकाना चाहिए।

2. (9) आयात के प्रति विदेशी संभरकों का भुगतान नीचे खंड-3 में यथा उल्लिखित स्थिति में माध्यम से किया जाएगा और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन प्रेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2 (10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहा तब संबंध है, इस विषय में त्रय संधिदा के अधीन मान के पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी पार्टी ही वाहनों को चुनने के लिए स्वतन्त्र होगी। पोतलदान जिस देश में संभरक रहते हैं वहां में या तीसरे देश से किया जा सकता है।

2 (11) बलिन लैण्ड सहित जर्मनी गणतंत्र संधि में खरीद के मामले में जिन संधिदाओं का मूल्य डी.एम. 1 मिलियन से अधिक है उनके लिए या अन्य देशों से खरीद के मामले में जिन संधिदाओं का डी.एम. तुल्यांक डी.एम. 1 मिलियन से अधिक है उनके लिए संभरित किए गए माल के निष्पादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निष्पादन गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए त्रय संधिदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें आवेश मूल्य का 10 प्रतिशत भी होना चाहिए। प्राधिकारपत्र जारी करने का अनुमोदन करने के लिए संधिदा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुबंध 4 के प्रपत्र में निष्पादन गारंटी ईईसी 1 अनुभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अन्य संधिदाओं के मामले में अर्थात् उन संधिदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए स्वतन्त्र है कि उमें विदेशी संभरक से निष्पादन गारंटी की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन, गारंटी निष्पादन का प्राप्प भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है। लेकिन, भारतीय आयातक को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि निष्पादन गारंटी से उभक्त यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उसको देय हो तो उसका करार क्रेडिट कान्सटान्ट पर बीट्रो-फराइ (ड्यूटेस बन्डेस बैंक फैंकफर्ट/मेन लेखा नं. 50409100 से सीधे किया जाना चाहिए।

2. (12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान 30 जून 1986 को पूर्ण हो जाने चाहिए। उपर्युक्त त्रय आदेश/संधिदाओं में पोतलदानों को पूर्ण करने और 30 जून 1986 तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होना चाहिए। यदि किसी मामले में यह आशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो पर्याप्त औचित्य देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू.न.ओ. बैंक बिल्डिंग, पर्सनियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय बृद्धि के लिए 30 अप्रैल 1986 तक आवेदन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा।

2 (13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य डी.एम. 2 मिलियन के बराबर रूपये से अधिक नहीं होता है, उनका मामले में भारतीय आयातक द्वारा त्रय संधिदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार में प्रस्तुत करना आवश्यक है। संधिदाओं को खंडी में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2(4) में वर्णित अर्हक संधिदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखना चाहिए।

खण्ड-3 विदेशी संभरकों को भुगतान—“विशेष” नारायण क्रियाविधि।

3 (1) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र:—जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य डी.एम. 2 मिलियन के बराबर रूपये से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति संभरकों के साथ संधिदाएं निर्णीत हो जाने के 15 दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी.एम. 2 मिलियन के बराबर रूपये से अधिक होता है (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर) उसके प्रति की गई संधिदाओं के के. एफ. डब्ल्यू. के अनुमोदन की सूचना देते हुए भारत

सरकार के पत्र देखिए उपर्युक्त पैरा 2(5)(ग) की विधि से 15 दिनों के भीतर इनमें से जा भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी सम्बद्ध विदेशी सभरक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ई ई सी-1 अनुभाग नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(क) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य डी एम 2 मिलियन के मूल्य रूप में अधिक नहीं होता उनके लिए की गई सविदाओं के सम्बन्ध में :—

(1) क्रय आदेश की तीन प्रतियां, और विदेशी सभरकों द्वारा क्रय आदेश के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो प्रमाण आयातक एवं सभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां साक्ष्योक्ति प्रतियां या भारतीय अधिकृतियों को दिए गए आदेश और ऐसे अधिकृतियों द्वारा की गई पुष्टि रसीदों नहीं हैं।

या

क्रय सविदा की तीन प्रतियां जो भारतीय आयातक और विदेशी सभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां भारतीय अधिकृतियों को दिए गए आदेश की साक्ष्योक्ति प्रतियां और ऐसे अधिकृतियों द्वारा की गई पुष्टि रसीदों हैं।

(2) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र (तीन प्रतियां)।

(3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले, प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के मामले में लागू नहीं)।

(4) लागत और भाड़ा सविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी के वचनपत्र की तीन प्रतियां देखिए उपर्युक्त पैरा 2(7)।

(5) इस संबन्ध में तीन प्रतियों में प्रमाण-पत्र की विदेशी सभरकों से तुलनात्मक बोलियों प्राप्त करने के बाद आदेश दिए गए हैं, देखिए उपर्युक्त पैरा 2(3)।

(6) इस संबन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि लाइसेंस के अधीन आने कोई भी सविदा नहीं की जाएगी, देखिए उपर्युक्त पैरा 2(13)।

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के तुल्य रूप में अधिक होता है उसमें दी गई सविदाओं के सम्बन्ध में :

पहले भेजे गए सविदा दस्तावेजों (जिनके संबंध में के. एफ. डब्ल्यू. का अनुमोदन वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा) देखिए उपर्युक्त पैरा 2(5)(ग), अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :—

(1) अनुबंध-2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में)।

(2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के मामले में लागू नहीं) और

(3) लागत और भाड़ा सविदा के मामले में भारतीय बीमा कंपनी के वचनपत्र की तीन प्रतियां, देखिए उपर्युक्त पैरा 2(7)।

3 (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

3. (3) साख-पत्र खोलना।

साखपत्र इस प्रयोजन के लिए पश्चिम जर्मनी में मनोनीत निम्नलिखित आठ बैंकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकार पत्र के बत पर खोला जा सकता है :—

(1) दि बेयरिस् बेरिन्स बैंक, म्युनिख।

(2) दि कामस बैंक, ए. जी. फ्रैंकफर्ट।

(3) दि ड्यूबोने बैंक, ए. जी. हैम्बर्ग।

(4) दि ड्रेम्डन बैंक ए. जी. गाल्सगेरोज 7 8, 6, फ्रैंकफर्ट/मेन-1।

(5) स्टेट आफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट बैंक।

(6) बर्लिनर इन्डिस् गेसस शेफ्ट, फ्रैंकफर्ट बैंक।

(7) बेरिन्स एण्ड वेस्ट बैंक, हैम्बर्ग।

(8) बैंक फार जोमियन्स रिट्सकाफ्ट (बी एफ जी)।

(9) बर्लिनर बैंक, एक्टिवजैमेल्सफेफ्ट, ए. जी. बर्लिन।

आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के) और उनके बैंकों को उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित नौ बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

3. (4) (क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रूप या इससे कम है उसके प्रति आदेशों के मामले में पक्के आदेश देने की विधि से या

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 2 मिलियन के बराबर रूप में अधिक है उसके प्रति सविदा के मामले में वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सविदा के अनुमोदन के पत्र की विधि से ऋण इनमें जो भी मामला हो उसमें 15 दिनों के भीतर प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर आयात नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन समझा जाए।

3. (5) बैंक गारंटी वह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादित करनी चाहिए।

जहां कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी जिस धनराशि के लिए विदेशी मुद्रा/साखपत्र मांगा गया है उसका तुल्य रूप के चांत्तक धनराशि के लिए प्रामाणिक तथा वचनबद्धता खर्चों और इसके अतिरिक्त व्याज तथा अनुबंध-5 में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों के लिए इस धनराशि के एक प्रतिशत के लिए होनी चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड-15 के अंतर्गत राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट दर होगी। यह दर का तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है। लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेख में लप्या वित्तियेप करने के लिए तुल्य रूप की गणना विदेशी सभरक को भुगतान की व्यवस्था करने समय जर्मनी बैंक द्वारा खर्च की गई डी एम धनराशि के लिए मिश्रित दर पर करनी होगी अर्थात् या तो डी एम में, यदि विदेशी सभरक पश्चिमी (बर्लिन लैण्ड सहित) में रहता है या समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-72 सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी सभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान को प्रभावी करने के लिए डी एम धनराशि में आने नाटिस जारी होने तक इस संबंध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा।

3 (6) प्राधिकारपत्र जारी करना :—

यदि उपर्युक्त पैरा 3(1) में निर्दिष्ट दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में आयातक का भारतीय बैंक

द्वारा खोले जाने वाले 'विशेष' साखपत्र के आधार पर विदेशी सभरकों को निर्धारित धनराशि तक भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करने हुए, वित्त मन्त्रालय (लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक), आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक ब्रिन्डिश, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, पश्चिमी जर्मनी में नामित वाणिज्यिक को एक प्राधिकारपत्र (अनुबंध-4 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकार पत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंस धारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकार पत्र की एक प्रति के साथ साखपत्र खाने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को हमारे द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ मूल प्राधिकार पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक को भेजने के लिए आदेश देने हुए भेजा जाएगा (ऐसा निर्देशन अनुबंध-5 के अनुसार होगा) इसकी एक प्रति आयातक को भी भेजी जाएगी।

तब तक इस कठिनाई में तथा उल्लिखित प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक में सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय में सीधे प्राप्त न कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारी का सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए।

(7) पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक में 'विशेष' साखपत्र प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, यू सी ओ बैंक ब्रिन्डिश पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली का सूचना देते हुए खोला जाना चाहिए। अन्यथा पहले ही जारी किया गया प्राधिकार पत्र वैध नहीं समझा जाएगा।

(8) अपेक्षित दस्तावेजों और विवरण पत्रों को एकत्र करने पर पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विदेशी सभरकों को भुगतान किए जाएंगे। जिस मामले में विदेशी सभरक जर्मनी गणतंत्र सच (बर्लिन लैण्ड सहित) से अन्य देश में रहता है उसमें भी समझौते की बातचीत और दस्तावेज का भुगतान पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किए जाएंगे। पश्चिम जर्मनी में नामित, वाणिज्यिक बैंक पश्चिमी जर्मनी प्राधिकारियों से डी एम धनराशि की अदायगी प्राप्त करेगा। जर्मनी गणतंत्र सच से अन्य देशों द्वारा सभरण के मामले में पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक विदेशी सभरकों को जिस देश में वे रहते हैं, उसी देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई धनराशि की अदायगी डी एम जर्मनी के प्राधिकारियों से प्राप्त करेगा।

(9) जर्मनी गणतंत्र सच में भुगतान के लिए और तीसरे देश में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी जर्मनी के बैंक द्वारा किए गए आनुषंगिक बैंक खर्चों जिस मामले में भी लागू होंगे वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक को सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना प्रेषित किए जाएंगे।

खण्ड-1 सरकार के लेखों में रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व

(1) बर्लिन लैंड सहित पश्चिमी जर्मनी से और अन्य देशों से आयातों के दोनो मामलों में पश्चिम जर्मन के नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मूल लेखान दस्तावेजों भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजने चाहिए। दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परकाय्य दस्तावेजों के मेट को लाइसेंसधारी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि पश्चिम जर्मन नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जर्मनी के सभरकों को चुकाई गई डी एम धनराशि के बराबर रुपया या जर्मनी के सम्बद्ध बैंक द्वारा तीसरे देश में सभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने में खर्च की गई डी एम धनराशि और इसका एक प्रतिगत आनुषंगिक तथा और वषण-बद्धता खर्चों के लिए और विदेशी सभरक का भुगतान करने की तिथि में या के एक उल्लेख द्वारा पदनामित बैंक का प्रतिपूर्ति की तिथि इनमें जो भी पहले हो, से सरकार के लेखों में रुपया जमा करने की तिथि तक (दोनों दिन मिलाकर) की अवधि के लिए उपर्युक्त कुल धनराशि ब्याज खर्चों आयातक से प्राप्त कर लिए जाते हैं और सरकारी लेखों में जमा किए

गए हैं। सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार ब्याज खर्चों की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी, 1 सितम्बर, 1983 को या उसके बाद सरकारी लेखों में जमा करने की दर —

(1) जहां सभरक को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर में निक्षेप किए जाते हैं या के एक डब्ल्यू द्वारा नामित बैंक को प्रतिपूर्ति की तिथि पहले हो, इनमें जो भी पहले हो।

(2) जहां सभरक का भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर रुपया निक्षेप किया जाता है या के एक डब्ल्यू द्वारा नामित बैंक को प्रतिपूर्ति की तिथि इनमें जो भी पहले हो।

(क) पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत

विदेशी सभरकों का विदेशी मुद्रा के तुल्य रूप में किए गए भुगतान की गणना के लिए रूपवाई जाने वाली बित्तियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में तथा निर्धारित मिली जुली दर हागी या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुद्रा बित्तियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हो सकती है। भारतीय सम्बद्ध बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि आयातकों को मूल पातलदान दस्तावेजों के सोपने से पूर्व यह सुनिश्चय कराए कि देय धनराशि ठीक प्रकार से सरकारी लेखों में जमा करा दी गई है। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उनके बैंकरो से दस्तावेजों को लेने से पूर्व सरकारी लेखों में देय धनराशि ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है।

(2) उपर्युक्त 4 (1) में बिचार किए गए निक्षेपों की धनराशि या ता रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में नकद जमा की जा सकती है या यदि वह सुविधा-जनक न हो तो वह धनराशि अधिकर्ता स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-7 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31 मई, 74 और सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5 अक्तूबर, 71 द्वारा तथा वर्णित सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई टी सी (पी एन)/88 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 के अनुसार अपेक्षित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनराशि जमा करने के लिए लेखा शीर्षक "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज बी" डिपोजिट्स नोट बियरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स-843 सिविल डिपोजिट्स डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्च्युट्री एक्सेडि ज़ायरेक्ट पेमेन्ट प्रोसीजर डिपोजिट्स फार कोस्ट आफ सप्लाईज एण्ड इन्विपमेंट ऑक्टेटेड अडर रि बैस्ट जर्मन कैपिटल गुड्स क्रेडिट 15 फार 1983-84 (डी एम 25 मिलियन क्रेडिट)

(3) धन परचण सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 में निर्धारित किए गए आधान प्रपत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

(4) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 में चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली-6 की डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के मध्य में सूचना जिस भारतीय बैंक ने गारंटी जारी की है उसके द्वारा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, यू सी ओ बैंक ब्रिन्डिश, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को पश्चिमी जर्मनी के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना टिप्पणियों का पूर्ण न्यौरा देने हुए अग्रोषण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

(5) केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा करने और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68 विनाक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्हों से लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी पंजीकृत कराना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित "एम" प्रपत्र भी भरना चाहिए।

(6) एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने के बाद और दस सप्ताहों के भीतर आयातकों/बैंकों द्वारा लेखों में जमा कर देने पर प्राप्त किए गए आयात माल और जमा किए गए रुपए के ब्यौरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू गी ओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को अनुबंध-6 में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय उनका सत्यापन करके जहाँ आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को रिहा करने के लिए व्यवस्था कर सकें।

अनुबंध 5 सविद्या में परिवर्तन

संविदाओं की माल की सूची, शर्तों, या भुगतान की अनुसूची, माल के मुख्य भाग से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के० एफ० डब्ल्यू० प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके परिणामस्वरूप चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसको स्थगित करना पड़े। आयातकों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2(5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकार/के० एफ० डब्ल्यू० के अनुमोदन के लिए कार्यवाही हेतु ऐसे परिवर्तन की सूचना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (ई ई सी-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक) को तुरन्त देनी चाहिए।

अनुबंध 6 रिपोर्ट भेजना

आदेश देने, माल की सुपुर्वगी, विदेशी सभरकों को भुगतान आदि को प्रदर्शित करने हुए लाइसेंस के जारी होने की तिथि से प्रारंभ करने अनुबंध 7 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्ट को दो प्रतिवियों में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ई सी-1 अनुभाग) कमरा सं० 69, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए और इसको भेजना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि संविदा के अधीन सभी पोतलदान और सभी भुगतान पूर्ण न कर लिए जाएं। बीस लाख डी एम के मुख्य रुपए (राजस्व शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर) से अधिक के आबंटन के मामले में ऊपर उल्लिखित त्रैमासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबंध 8 में निर्धारित प्रपत्र में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतिवियों में) भी याद कोई विशेष घटना हो तो परियोजना की प्रगति पर और परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय-समय अनुसूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आयात करने वाली भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतिवियों में) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम तीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

अनुबंध 7 विविध प्रावधान

7. (1) लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी शर्त से सभरकों को अग्रगत कराना ही चाहिए जो लेन देन का अनुपालन करने में सभरकों को प्रभावित करें।

(2) विवाद.—यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयातक और विदेशी सभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

(3) अनुदेशों का पालन.—आयात लाइसेंस में संबंधित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के संबंध में के० एफ० डब्ल्यू० प्राधिकारियों के साथ 25 मिलियन डी एम के पूंजीगत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अनुदेश और आदेश का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

(4) अतिरिक्त या उल्लंघन.—उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

(5) अनुबंधों की अनुसूची.—

अनुबंध-1 परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र

अनुबंध-2 प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र

अनुबंध-3 बैंक गारंटी का प्रपत्र

अनुबंध-4 निष्पादन गारंटी का प्रपत्र

अनुबंध-5 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुबंध-6 प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र

अनुबंध-7 बैंक गारंटी की रिहाई के लिए रुपया निर्जों की रिपोर्ट व आवेदन पत्र का प्रपत्र

अनुबंध-8 त्रैमासिक रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

अनुबंध-9 (अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र) बीस लाख रुपए से अधिक के मामले लिए लागू है।

अनुबंध-1

परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र

क्रेडिटन्टास्ट फर वाइडोफबो

6, फैंक फर्ट/मेन, जर्मनी संघीय गणराज्य पापमेन गरिनेन्स्ट्रेसी
5.9 जर्मन पूंजीगत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए

आवेदन पत्र

परियोजना आंकड़ों

(1) आवेदक (फर्म)

(क) पूंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पता)

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र मस्थान

(ग) व्यापार लाइन/उद्योग की शाखा

(घ) कंपनी के भागीदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) वित्त पोषित किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्म

(3) पूंजीगत माल के चुनाव का आधार-कृपया अपनाई गई अधिकतम क्रियाविधि का संकेत करें। चूंकि पूंजीगत माल ऋण किसी भी देशों से खरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इन मध्य में से केंद्र किया जाना चाहिए कि विदेश देशों में निविदा के संबंध में पृष्ठछाछ की गई/बाछ की गई थी और वह आधार क्या जिसके लिए विशेष सभरक का चुनाव किया गया है।

(4) सभरक (नाम और पता)

(5) संपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित आंकड़ों के विश्लेषण के साथ संपूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कीमत.—

—मृमि एवं भवन

—मशीनरी एवं उपकरण

—परिचालन निधि

—विविध

* (7) संपूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्रोत (वित्तदान) के माधनों में संबंधित मात्रित विवरण से इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कृपया वित्तदान है और इस आवेदन पत्र के अंतर्गत न आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी कर ली/प्राप्त कर ली गई हैं।

(8) प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र

(9) सन्तुलन पत्र एवं लाभ तथा हानि के लेखे के साथ दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट। यदि उपलब्ध हो तो नकद-गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) क्षमता

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उपयोग

(ख) उपयोगार्थीन मामलों में कृपया मुख्य कारण दें।

(11) बिक्री (गत दो वर्षों)

(12) चिन्तिमणि किए जाने वाले उत्पादों की साफ्ट स्थिति (यदि संभव हो तो भूतकालीन एवं सम्भाव्य विकास के आकड़ों को प्रदर्शित करें)।

(13) रोजगार

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी

(14) कच्चे माल के संभरण स्रोत

(15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारणी।

अनुबंध-2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

महायत्ता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

यू सी ओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट

नई दिल्ली।

विषय :-

1983-84 (डी एम 25 मिलियन क्रेडिट) के लिए पश्चिम जर्मनी प्रयोग माल क्रेडिट के अंतर्गत का आयात।

.....

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मनी प्रयोग माल क्रेडिट के अंतर्गत से का आयात करने के संबंध में इस निम्नलिखित व्यौरा आपको देने हैं ताकि आप के माध्यम से वैपरीमे वेरेंस म्युनिख अथवा कार्मिअ बैंक ए जी फ्रैंकफर्ट अथवा ड्यूस्सलैंड बैंक ए जी हम्बर्ग अथवा ड्रेसे-डेनर बैंक ए जी शाल्लेमेनलेज 7-8, 6-फ्रैंकफर्ट मेन-1 या फ्रैंकफर्ट बैंक फ्रैंकफर्ट/एम एम मेन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रैंकफर्ट या वेरिअ एंड वेस्ट बैंक हम्बर्ग अथवा बैंक फर जर्मिअ अथवा वर्तमचैफट (बी एफ जी) या बनिनर बैंक अफ्टिनजैवेल चैफट ए जी बनिन से साख्यपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकें।

(क) आयातक का नाम और पता

(1) क्या सांख्यिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र संस्थान का है।

(2) उद्योग की श्रेणी जिससे वह संबंध रखता हो।

(3) वह राज्य जिसमें स्थित है।

(ख) लाइसेंस की संख्या दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की कोटि प्रति संयमन की जानी चाहिए)।

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् (लागत बीमा भाड़ा या नागत भाड़ा) किसी भी मामलों में (केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकारपत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए) को वशति हुए संभरक द्वारा किए गए और स्वीकार किए आवेदों का विदेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र के पत्रके आदेश (संभरक के पुष्टि-करण आदेश के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से चार भाग के भीतर दे दिए गए हैं। यदि 4 मास की निर्धारित अवधि के बाद आदेश दिए गए हैं तो जैसा भी मामला हो। मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के पत्र/वित्त मंत्रालय के पत्र की एक ऐसी प्रति संयमन की जानी चाहिए जिसमें आवेदन देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है।

(ङ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाणपत्र कि समुद्रपार संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद पत्रके आदेश दिए गए हैं। और यह कि न्यूनतम उपयुक्त तकनीकी दाम स्वीकार कर लिए गए हैं। यदि तुलनात्मक बोली प्राप्त करना संभव नहीं है जैसा एकाधिकार मद, तो इसके लिए पूरे औचित्य दिए जाने चाहिए।

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(छ) वास्तविक विदेशी मुद्रा में वह धनराशि (उस देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाता है जिसमें संभरक रहता हो) जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है (अभिकरण के कर्मेशन को छोड़कर)।

(ज) विदेशी मुद्रा में अभिकरण के कर्मेशन की धनराशि और भारतीय अभिकर्ता का नाम और पता।

(झ) ऐसे मामले में जहां संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित है, तो संभरक के उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसमें वेस्ट जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जाती है।

(ञ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की अनुमानित तिथि।

(ट) संविदा के अस्तित्व भुगतान के लिए पड़ने वाली सम्भावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

(ठ) 1 मिलियन डी एम के बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले में यह बताते हुए एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि आयात लाइसेंस के मद्दे सभी संविदाएं पूरी कर दी गई हैं और प्राप्त कोई भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा साख्यपत्र खोला जाएगा।

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुमूर्जित बैंक का नाम और और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा के लिए दी गई बैंक गारंटी सं दिनांक और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के

अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिकरण व्यय निर्मित की गई है, सत्य है।

मध्याह्न

प्रति बैंक की सूचनाएं प्रेषित

लाइसेंसधारक

अनुबंध-3

गारंटी बॉण्ड

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे सरकार कहा गया) पश्चिम जर्मनी, पूर्वागत माल क्रेडिट 1983-84 की शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम से आयातक अनुमति में दिनांक को जारी किया गया लाइसेंस स. का पालन करते हुए के द्वारा बाद में इसे "आयातक" कहा गया है। (..... के आयात के लिए भुगतान के लिए राजी होने हुए विदेशी मुद्रा में उपयुक्त धनराशि का संकेत करे) आयात के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मंजूरित (वेस्ट जर्मनी में शण्डियस बैंक का नाम) बैंक द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की जा लू परिवर्तित दर पर जो संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिष्कृत किया जाता है और इसके साथ 1 प्रतिशत की विदेशी सभरक को लिए भुगतान की तारीख तक सरकारी लेख में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक या के एफ. डब्ल्यू द्वारा नामित बैंक की प्रतिभूति की तिथि तक इनमें जो भी पहले हो प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से और इसमें अधिक की अति के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से व्याज के भुगतान के साथ पं.मार्ग की पावती की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उस क्रेडिट के अंतर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं।

वेस्ट जर्मनी में नामित वणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को केवल तभी वापस जाएगा जब कि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपये जमा कर लिए गए हैं।

2. हम दि बैंक सरकार जहां और जैसा भी, समय-समय पर निर्देश दे, आयातक द्वारा समय-समय पर सरकार को दे जाने वाली किसी भी प्रकार की धनराशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी सभरक को भुगतान करने की तिथि से इस पर प्रथम तीन दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक और इससे अधिक सभरक के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि को रुपये में अधिक नहीं है, आयातक द्वारा भुगतान करने में देर रहेगी तो इसकी भी शर्त में सरकार को दे रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे बैंक द्वारा दी जानी है, इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3 हम बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के प्रत्यक्ष मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या घटने से को छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

1 हम बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि गारंटी में जो कुछ निहित है वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूर्ण शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगे और उसे जब तक कार्यक्षिप्त रखा जाएगा जब तक सरकार के अंतर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया वेब पूर्णरूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांग पूर्ण न हो गई हो या उन्मुक्त न हो गई हो।

5. हमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि बैंक के परिवर्तन में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और दि बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति का किम्वं समय या समय-समय के लिए स्थगित करने और उपयुक्त मामलों के मद्दे में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान को दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी में उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानती में संबंधित हो बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 अन्त में हम बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना मुद्रा में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अंतर्गत रूप (इसमें व्याज तथा अन्य प्रभार भी शामिल है, इस गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत में ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जानी) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और यह दिन माम 198 तक, जब तक इसकी तारीख में डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अंतर्गत मांगे पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाद दूसरे डेढ़ वर्ष के भीतर अर्थात् तक उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्रवाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अंतर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और हम लोग हमारे अन्दर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

..... दिन का दिनांक

नाम्ने श्री के

(बैंक लि.)

द्वारा नाम और ओहदा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

8. यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र को वैध रखने तक की तारीख में लागू होगी।

टिप्पणी—(1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यक्षिप्त होने वाली है, इसके मूल्य का भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा व्याज निर्णित किया जाना है।

(2) बैंक गारंटी का मूल्य देखे उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 7 जो 1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् संविदा के वास्तविक लागत तथा भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा मूल्य होगा और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को मुद्रा विनिमय (बीमा शुल्क) की प्रचलित दर पर परिवर्तित और शामिल किया जाएगा।

अनुबंध-4

(निष्पादन बाण्ड)

साधनधारी का पता मूल्य
के ठेके पर (परियोजना)
(के लिए समस्त (जिनकी
बाब में ठेकेदार के नाम से पुकारा जाये) के साथ
को आपके ठेका करने के विचार हेतु

और चूंकि ठेके की यह एक शर्त है कि ठेके के मूल्य का
प्रतिशत का एक निष्पादन बाण्ड दिया जाय,

हम, अधोहस्ताक्षरी बैंक, उपर्युक्त संविदा के अधीन सभी आपसियों तथा
प्रतिवाधियों को दूर करते हुए, आपकी निश्चित घोषणा के मद्दे कि ठेकेदार
ने अस्वीकार कर दिया है अथवा ऊपर उल्लिखित ठेके का निष्पादन करने
में असफल रहा है (रूपरे) (एवंकों
में) की सीमा तक आपके द्वारा मांगी गई किसी भी धनराशि का आपको
प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी विलम्ब के एतद्वारा अपरिवर्तनीय
तथा स्वतंत्र रूप से आपकी भुगतान करने के लिए गारंटी देते हैं।

इस गारंटी के अधीन यदि कोई क्लेम किया जाता है तो
नाम में भुगतान क्रेडिटान्सटाल्ट पर बैङ्कियूफ़ेवाड फैंकफर्ट/मैन (एकाउन्ट
नं. 50 409 100 ड्यूटसच बुनडेसबैंक, फैंकफर्ट/मैन के साथ) प्रभावित
होगा।

यह गारंटी (तिथि) को
समाप्त होती और उस तारीख तक हमें कोई भी क्लेम रजिस्टर्ड पत्र
अथवा केबल द्वारा अग्रण्य प्राप्त होना चाहिए।

यह मान लिया गया है कि आप हमके अधीन मांगी गई कुल धनराशि
के भुगतान समाप्त होने पर आप यह गारंटी वापस हमको कर देंगे।

तिथि बैंक

अनुबंध-5

प्राधिकार पत्र की संख्या

स.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(प्राथमिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक...

सेवा में,

(मनोनीत बैंक का नाम और पता)

जर्मन संघीय गणराज्य

विषय:- जर्मन संघीय गणराज्य से डी०एम० 25 मिलियन पूंजीगत
माल क्रेडिट दिनांक 12-9-83 (ए एल-8265852) आयात
साइसेंस सं दिनांक सीधे भुगतान क्रियाविधि
के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान।

प्रिय महोदय,

उपयुक्त क्रियाविधि की शर्तों के अनुसार, हम आपको एतद्व-
द्वारा संबंधी
..... द्वारा की गई संविदा के मद्दे
..... के आधान के लिए
1526 GI/84-2

द्वारा खोले गए साख-पत्र के अंतर्गत संबंधी
को का भुगतान करने के
लिए डी एम में जितनी भी धनराशि आवश्यक हो खर्च करने के लिए
प्राधिकृत करने हैं।

2. चूंकि धनराशि डी०एम० 25 मिलियन पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत
माल क्रेडिट के अंतर्गत वित्तदान की जाती है, वस्तावेज प्रस्तुत करने पर
उनके विषय में बातचीत करें और साथ ही साथ क्रेडिटस्टाल्ट पर भी
डरफर्बों, फैंकफर्ट में अदायगी प्राप्त कर संभरक को भुगतान करें। यदि
के एक डब्ल्यू किसी कारण से धनराशि की अदायगी नहीं कर रहा है तो
आप आवश्यक अदायगी के लिए इस विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. प्रत्येक भुगतान के बाब जहाजरासी एवं अन्य प्रकार के प्रलेखों
(परकाम्य) को सीधे भेजे जाए और प्रलेखों
(अपरकाम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श हमें सूचनाएं
भेजी जाए।

4. उपयुक्त साख पत्र के अंतर्गत आपके बैंक प्रभार
... के भारत द्वारा जमा धन से आपके साथ ही तय किया जाएगा।

5. यह प्राधिकार 198 तक
वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति:- ।

1. एक प्रति भारतीय बैंक को।

2. आयातक को

3. के०एफ०डब्ल्यू०, फैंकफर्ट को इस मंत्रालय के पत्र सं.
..... दिनांक के अनुसरण में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के
अनुरोध पर तत्काल ही अतिशीघ्र अदायगी के लिए प्रबंध करें।

अनुबंध-6

विषय:- 1983-84 के लिए डी.एम.-25 मिलियन पश्चिम जर्मनी
पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत आयात साख पत्र खोलने के
लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

आयात लाइसेंस सं दिनांक

प्रिय महोदय,

..... से पत्र संख्या
..... दिनांक के संबंध में, जिसमें उन्होंने 1983-84
के लिए डी.एम. 25 मिलियन पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल
क्रेडिट के अंतर्गत आपके बैंक द्वारा साखपत्र खोलने की अनुमति मांगी
है, मैं उन्हें विदेशी संभरक को तक भुगतान की
व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करते हुए अधिक कार्य विभाग की पत्र सं.
..... दिनांक संलग्न करता हूँ।

(एक प्रतिरिक्त प्रति के साथ)

इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ
..... को भेज दिया जाना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए इस पत्र के जारी होने
की तारीख के तीन दिनों के भीतर आपको साखपत्र खोलने का अधिकार
दिया जाता है जो इसकी धनराशि से अधिक नहीं होगी

वाहिए । विनियम नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग-7 की कड़ीका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना प्रोहित है कि पोतलवान को अंतिम तारीख निश्चित होने के बाद साखपत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिनों से पहले नहीं है जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है या प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है इनमें से चाहे जो भी पहले हो वही होनी चाहिए । साखपत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उनके पास बैंड आयात लाइसेंस है ।

3. बैंक से पूछा जाए कि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बातचीत करें और साथ ही साथ के० एफ० डब्ल्यू० से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर भुगतान करें ।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आपके द्वारा की गई सविधा के अनुसार आप लेण्ड बॉलिन मॉडर्न जर्मन संघीय गणराज्य में संभरक के लिए डी.एम. में भुगतान की या अन्य देशों के विदेशी संभरकों के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान की और इसके साथ एक प्रतिशत के हिसाब में अनुवर्गिक और प्रभावी की प्रभावी बनाने के लिए (परिचय जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक का नाम) जमा करने की व्यवस्था करें । विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रूप द्वारा द्यूसखे मार्क में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य रूप की गणना भ्रगली सूचना के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना सं. 15-आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 28-1-72 एवं सार्वजनिक सूचना सं. 108-आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा संकेतित अदला-बदली की मिली-जुली दर से परिगणित की जाएगी । जब कभी विनियम की आई. एम. एफ. की सम दर में परिवर्तन होता है तो वो दर संशोधित है । संभरक की भुगतान की तिथि से और जिस निधि को समतुल्य रूपया जमा किया गया है (कोनो दिन मिलाकर) प्रथम तीस दिनों के लिए 12% वार्षिक दर में और इससे अधिक के लिए 18% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी सरकारी लेखों में जमा करना है । जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी(पीएन)/83 दिनांक 10-8-83 में दिया गया है और जो संभरक को भुगतान की तिथि में गिना जाएगा या के. एफ. डब्ल्यू. द्वारा नामित बैंक को अदायगी की तिथि में गिन जाएगा, इनमें जो भी पहले हो । आयातक की लदान प्रलेखों की दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी होगी ।

5. ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में नकद जमा की जानी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके नियंत्रता (आदेशक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 (आदेशिनी और पाने वाला) के नाम निकालने और भुगतान के लिए है, उसके द्वारा जमा की जानी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 द्वारा यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 233 आईटीसी(पीएन)/68, दिनांक 24 अक्टूबर, 68 एवं सख्या 112-आर टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5 अक्टूबर, 71 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें इसे जमा किया जाना है उसका लेखा शीर्ष, के-डिपोजिट एंड एडवांसमें—बी-डिपोजिट नाट विर्यग डब्ल्यूस्ट अंडर डायरेक्ट पेमेण्ट प्रोसीजर डिपोजिट फार क्राफ्ट आफ एन्वाइज एंड एक्स्पेंडिट आक्टेंड अंडर वेस्ट जर्मन कैपिटल गुड्स क्रेडिट 15 फार 1983-84 (डी०एम० 25 मिलियन) होगा ।

6. मनोनीत जर्मन बैंक में प्राप्त नोट का पूरा विवरण देने हुए एक अंग्रेजित पत्र के साथ रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूपया नकद में जमा करने

के मामले में आवाहन की एक मूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए :-

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

पू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

डिमांड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रूपया जमा करने के मामले में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 68 में बताया गया है, उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज की जा धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए ब्याज परिगणित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा किए गए समतुल्य रूप का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए ।

7. खोले जाने वाले साखपत्र में इस मबध में एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि विदेशी बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त कोई बाबा और/या गारंटी के निष्पादन में संबंधित बैंक गारंटी में होने वाले कोई दावे बीमा कंपनी और/या डी.एम. में गारंटी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को अवगत कराते हुए सीधे ही के. एफ. डब्ल्यू. (लेखा सं. 504,09100 ड्यूसखे बन्देसबके, फेल्फर्टेमिन) को प्रेषित किए जाने चाहिए ।

8. जिस विदेशी मुद्रा में प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, उसी में साख पत्र खोला जाना चाहिए ।

9. भारतीय अधिकारी का कमीशन, यदि कोई हो तो भारत में रूपय में अदा किया जाना चाहिए ।

10. कृपया इस पत्र की पाबसी भेजी जाए ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पत्र की संख्या की एक प्रति के साथ प्रति सूचना एवं उसके ऊपर दिए गए पत्र के संवर्ध में सर्वश्री को प्रेषित ।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-7

प्रपत्र

1. जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता ।
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य ।
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि ।
4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय में प्राप्त प्राधिकार पत्र के शरीर :-

(क) प्राधिकार पत्र की संख्या एवं दिनांक

(ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में) ।

5. प्रभावी किए आयातों एवं जमा किए गए रूपयों के व्यतिरे:-

(क) संभरक का नाम

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गई वार्षिक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)

(ग) वेस्ट जर्मनी में नामित बैंक द्वारा संभरक का किए गए भुगतान की तारीख

10. यदि प्रायास लाहसंस में शेष धन-राशि है तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है । यदि ऐसा है तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे प्रागे सविवा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है ।
11. समय-सारणी रखना, वास्तविक तिथियों के साथ मारणी की तुलना और समय मारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण है ।
12. यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारण सहित परिपोधित समय-मारणी ।

13. परियोजना की प्रगति :—

1. माल का सभरण (सुपुर्बगी की शर्तें)
2. स्थापना (क्रिस्म तथा कोटि)
3. प्रचालन (प्रतिष्ठित स्वीकृति, किए गए प्रयोग संचालन के परिणाम) ।

14. परियोजना की समापन तिथि ।

15. परियोजना की वार्षिक उलझने ।

16. लागत और वित्तीय योजना का कार्यन्वयन/

योजना की वास्तविक मूल्य के साथ तुलना ।

17. परियोजना के जालू करने से संबंधित कोई विशेष घटनाएं ।

18. परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियां) ।

टिप्पणी :— जो लागू न हो उसे काट दें ।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 83-ITC(PN)|84-85

New Delhi, the 5th February, 1985

Subject :—Licensing conditions for imports under West German Capital Goods Credit of DM 40 Million for 1982-83, DM25 Million for 1983-84, DM15 Million for 1983-84 and 60 Million for 1984-85.

File No. IPC|23(11)|84-85.—The terms and conditions governing imports under the West German Capital Goods Credit as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX

Conditions attached to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 40 Million for 1982-83; DM 25 million for 1983-84 DM 15 million for 1983-84 and DM 60 million for 1984-85.

I. (i) Where the value of allocation approved by the Capital Goods Committee exceeds the rupee equivalent of DM 2 million (the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962) the prior concurrence of the West German authorities[Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form at Annexure—I. Till such concurrence from West German authorities is communicated to the Licensing authorities (CCI&E) by the Department of Economic Affairs no import licence can be issued in favour of the Indian importer.

(ii) The licence shall bear the superscription "DM 25 million West German Capital Goods Credit for 1983-84." The licence code for the first and second suffix will be "S|GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the Import Licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channel. Payments towards Indian Agent's commission, if any, should be made in Indian rupee to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

(iv) The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country. The overseas supplier is, therefore, free to procure material, etc. from a third country, if found necessary, for the execution of the contract.

(v) The minimum and the maximum amounts for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 and DM 5,000,000 respectively. However, in exceptional cases, the maximum limit can be relaxed by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance upto DM 7,000,000 (rupees equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) which rate of exchange should be indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports).

(vi) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2 (xii) below, whichever is less subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

(vii) Firm orders (meaning thereby purchase Order by the Indian licensee on the foreign supplier supported by order confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier) must be finalised within a period of 4 months from the date of issue of the import licence (vide para I (ix) below). Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

(viii) If firm orders, as explained in para I (vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the Licensee should submit to the Chief Controller of Imports & Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of

Economic Affairs (EEC. I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension will the authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.

1. (ix) It will be in the interest of the licensee to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

1. (x) In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licences, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para I (viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

Section II : Special points to be kept in view while concluding purchases contracts.

2. (i)—The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable to the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purpose of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

2. (ii) Supply orders should be placed either on CIF or on C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

2. (iii).—It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers. In this connection it may be noted that the Indian importer is free to import from any country of his choice, as approved by the Capital Goods Committee of the Government of India.

2. (iv).— Minimum value of eligible contract.— Provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000 (in the case of purchases made wholly from the Federal Republic of Germany) or equivalent of DM 30,000 (in the case of purchases made wholly or partly from countries other than the Federal Republic of Germany), it is permissible for the importer to enter into individual purchase contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2 (xiii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million.

2. (v) (a) The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India and the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 25 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 2 million or less calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs), the approval of the contracts will not be specifically intimated to the importer. Once the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KfW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KfW also unless the KfW raises any objection subsequently in which even the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 2 million. (Calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), the approval of the KfW will be first obtained by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract alongwith a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from Foreign suppliers are required to be sent by the Indian importers to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC. I Section) Room No. 69, North Block, within a fortnight from the date of conclusion of the purchase contract.

2. (vi) Where contract is placed on CIF basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims, would be made directly in DM to KfW (AC/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (vii) Where contracts are placed on C&F basis, the marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However the

Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (EEC. I Section) along with the contract documents :—

"We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers for any replacement, that may be necessitated by loss or damage to goods".

2 (viii) As the contracts are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2 (ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charges in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2. (ix)—Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for this purpose.

2. (x) As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free to choose the carriers. Shipment can be made from the country in which suppliers are situated or from a third country.

2. (xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin or, in the case of purchases from other countries, for contracts the DM equivalent of whose value exceeds DM 1 million, the purchase contracts should provide for furnishing of performance guarantee by the foreign supplier in regard to the performance of the goods supplied (covering 10 per cent of the order value). The performance guarantee in the proforma at Annexure—IV should be submitted to EEC. I section on submission of contract documents for request for issuance of letter of authority (in the case of other contracts, from namely for contracts whose value is less than the limit indicated above, the Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign suppliers). The form of the performance guarantee can however be settled by the Indian importer with the foreign supplier by mutual consent. It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditanstalt für Wiederaufbau (Acct. No. 50409100 with Deutsche Bundesbank Frankfurt/Main).

2. (xii) Payments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 30th June, 1986. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 30th June, 1986. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts & Credit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 30th April, 1986. Such requests will be considered on merits.

2. (xiii) In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million the purchase contracts are required to be submitted by the Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

Section III—Payment to foreign suppliers—"Special" Letter of Credit Procedure

3.—(i) Request for issue of Letter of Authority

Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 2 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) or within a fortnight from the date of communication of the Government of India (vide para 2(v) (c) above) conveying the approval of KIW to the contracts placed against an import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 2 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), as the case may be, the licensee should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, EEC—1 Section, North Block, New Delhi with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 2 million.

(i) Three copies of the Purchase Order and and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers respectively or photo copies thereof. Attested copies or the orders placed on the Indian Agents and confirmation by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier or photo copies thereof of an Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such agents are not acceptable.

(ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.

(iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure—III from an Indian Bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector Imports).

(iv) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2 (vii) above.

(v) A certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign supplier.

- (vi) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2 (xiii) above.

- (b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 2 million

In addition to the contract documents furnished earlier (in respect of which KfW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) vide para 2(v)(c) above, the following documents should be submitted :

- (i) A request (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.
 - (ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange. (not applicable in the case of Public Sector Imports); and
 - (iii) In the case of C&F contracts, three copies of the under taking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.
3. (ii) It is clarified that in the case of public sector imports, no bank guarantee is required.

3 (iii) Opening of Letter of Credit

Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority on any one of the following 9 commercial banks in West Germany designated for this purpose :—

- (i) The Bayerische Vereinsbank, Munich.
- (ii) The Commerz Bank, A.G. Frankfurt
- (iii) The Deutsche Bank A.G. Hamburg
- (iv) The Dresdner Bank A.G., Gallusanglage 7-8, 6, Frankfurt/Main-I
- (v) State Bank of India, Frankfurt
- (vi) Berliner Handels Gesellschaft Frankfurter Bank
- (vii) Vereins-Und-West Bank, Hamburg
- (viii) Bank fur Gemein—Wirtschaft (Bfg)
- (ix) Berliner Bank, Aktiengesellschaft, A.G., Berlin.

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the nine mentioned in para 3(iii) above.

3. (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 2 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose licence value exceeds the rupee equivalent of DM 2 million as the case may be, deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

3. (v) Bank Guarantee-amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is sought plus 1 per cent of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure-V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act 1962 on the date of issue of Import Licence. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the DM amount spent by the designated commercial banks in West Germany in arranging payments to the foreign suppliers i.e. either in DM of the foreign supplier is situated in West Germany (including Land Berlin) or the DM amount for effecting payment in the currency of any other country in which the foreign supplier is located in terms of the public notice No. 15-ITC(PN) 72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN) 72 dated 21-7-1972 and 8-ITC(PN) 76 dated 17-1-1976 as amended from time to time. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

3. (vi) Issue of Letter of Authority.

If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts & Audit), Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated commercial bank in West Germany (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the foreign suppliers on the basis of a "Special" letter of credit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial bank in West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian Licensee. The original Letter of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian Bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original letter of Authority to the designated commercial bank in West Germany along with Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be as in Annexure-V). A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No Bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para has been received by such a Bank directly from the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

3. (vii) The "Special" Letter of Credit on the designated commercial Bank in West Germany should be opened within thirty days from the date of the issue of Letter of Authority under intimation to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi. Otherwise the

Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

3. (viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commercial Bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. Even where the foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany (including Land Berlin) the negotiation and payment of documents would be done by the designated commercial bank in West Germany. The designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of supplies by countries other than the Federal Republic of Germany, the designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3. (ix) Incidental Bank charges incurred by the Bank for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial bank in West Germany through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV—Responsibility for Rupee Deposits into Government Account.

4. (i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial Bank of West Germany both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries, to the concerned bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents of the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier or the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the designated commercial bank in West Germany plus 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier or the date of reimbursement by KfW to the designated bank whichever is earlier to the date of deposit of the rupee equivalent into Government account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 31-ITC (PN)/83 dated 10-8-1983 the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made in to the Government Account on or after 1st September, 1983.

(i) Where deposits are made within 30 days after, from the date of payment to the 12 per cent per annum supplier or the date of reimbursement is earlier by KfW to the designated Bank whichever is earlier.

(ii) Where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier or the

date of reimbursement by KfW to the designated Bank whichever is earlier.

(a) for the first 30 days 12 per cent per annum.

(b) for period in excess of 30 days 18 per cent per annum.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange of laid down in CCI&E's public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by the Government from time to time through public notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original shipping documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

4. (ii) The deposits envisaged in para 4 (i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amounts may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC (PN) 68 dated the 24th October, 1968 as amended vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is "K-Deposits and advances-Deposits not hearing interest-843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad-3 Direct Payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XV for 1983-84 (DM 25 million Credit)".

4. (iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974.

4. (iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which had issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi 110001 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German bank.

4. (v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC (PN) 68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4. (vi) After the imports under a licence are completed and the importers/banks have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-VI to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

Section V—Alteration in the contract

Any material alteration in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KfW authorities, whether it results in earlier payments, or in postponement of payments.

Such alteration (s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi (EEC-I Section, North Block) for securing the approval of the Government of India/KfW in the same manner as explained in para 2(v) above.

Section VI—Reporting

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC-I Section Room No. 69, North Block), New Delhi showing progress of ordering delivery of goods, payments to foreign suppliers, etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 2 million [at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs)] the licensee should, in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure-VIII (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project along with annual Report (2 copies) of the Indian importing company for at least three years until completion of the project.

Section VII—Miscellaneous Provisions

7. (i) The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the Suppliers in carrying out the transactions.

7. (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importers and the foreign supplier.

7. (iii) Compliance with Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence for meeting all obligations under the DM 25

million Capital Goods Agreement with KfW authorities.

7. (iv) Breach or Violations

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7. (v) List of Annexures

- Annexure-I Project data Form
- Annexure-II Form of Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure-III Form of Bank Guarantee
- Annexure-IV Form of performance Guarantee
- Annexure-V Form of Letter of Authority
- Annexure-VI Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority
- Annexure VII Form of report of rupee deposit-cum-application for release of Bank Guarantee.
- Annexure-VIII Form submitting quarterly report.
- Annexure-IX Form of Half-yearly Progress Report (applicable to cases exceeding rupee equivalent of DM 2 million).

ANNEXURE I

PROJECT DATA FORM

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

6, Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany
Palmengartenstrasse 5-9.

Application for Foreign Exchange from German
Capital Goods Loan

PROJECT DATA

(1) Application (Firm)

- (a) Registered Office (address including State)
- (b) Public Sector or private sector undertaking.
- (c) Business Line/Branch of Industry.
- (d) Partners of Company.
- (e) Foreign Collaboration Agreement.

(2) Type of Capital Goods to be financed.

(3) Choice of capital goods based on—please indicate the procurement procedure followed. Since the Capital Goods loan is available for purchases from any country, an indication should be given whether tender enquiries were made/floated in various countries and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.

(4) Suppliers (name and address).

(5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required).

(6) Local and foreign exchange cost of the whole Project, with following break-down of figures

- Land and building.
- Machinery and equipment.
- Operating Funds.
- Miscellaneous.

(7) Local and foreign financial sources for the whole project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by this application are met).

(8) Letter of Intent for Industrial Licence received.

(9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.

(10) Capacity

- (a) Average utilization of existing capacity during the last two years.
- (b) In case of under-utilisation, please give main reasons.

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment

- (a) Present number of employees.
- (b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the project.

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject: Import offrom.....
under West German Capital Goods Credit
for 1983-84 (DM 25 Million Credit).

Sir,

In connection with the import of
from.....under the above mentioned West
German Capital Goods Credit, we furnish the follo-
wing particulars to enable you to issue the authority
for opening the letter of credit through.....on
the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerz-
bank A.G. Frankfurt of Deutsche Bank, A.G.
Hamburge or the Dresdner Bank, A.G. Gallusaliage
7-8, 6, Frankfurt/Main-I or the Frankfurter Bank,

Frankfurt/Main or State Bank of India, Frank-
furt or Vereins-Und West Bank, Hamburge or Bank
fur Gemeins-Wirtschaft (Bfg) or Berliner Bank,
Aktiengesellschaft, A.G., Berlin.

(a) Name and Address of the Importer.

- (i) Whether a public or private sector under-
taking.
- (ii) Category of industry to which it belongs.
- (iii) The State in which it is located.
- (b) Number, date and value of licence (photo-
stat copy of the licence should be attached).
- (c) Value in foreign currency and date of the
order placed and accepted by the suppliers,
indicating payment terms viz., (c.i.f. or
C&F) (In no case, Letter of Authority
should be applied for f.o.b. value only).
- (d) A certificate in duplicate that firm orders
(with suppliers order confirmation) have been
placed within a period of 4 months from
the date of import licence. If orders have
been placed after the stipulated period of
4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry
of Finance's letter authorising extension of
time for placing firm orders as the case may
be, should be attached.
- (e) A certificate in triplicate that firm orders
have been placed after obtaining compar-
able bids from overseas suppliers and that
the lowest technically suitable offer has
been accepted. In cast it is not possible to
obtain comparable bids, e.g. proprietary
item, full justification therefore should be
furnished.
- (f) Short description of the goods to be imported.
- (g) Net foreign currency amount payable to
Suppliers (to be expressed in the currency
of the country in which suppliers is locat-
ed) for which letter of authority is required
(excluding Agency Commission).
- (h) Amount of agency commission in foreign cur-
rency and name and address of Indian
Agent.
- (i) In case the supplier happens to be located in
a country other than West Germany, the
name of the suppliers bank to whom the
amount is to be remitted by the designated
Commercial Bank in West Germany should
be indicated.
- (j) Expected date of completion of delivery.
- (k) A schedule showing probable dates on which
payments under the contract will fall due.
- (l) In the case of import licence upto a value
which is equivalent to DM 1 Million, a cer-
tificate that all the contracts against the im-
port licence have been placed and that no
further contract will be placed.

The Letter of Credit will be opened through.

(Name and address of the Indian scheduled bank,
authorised) to deal in foreign exchange.....

and the Bank Guarantee No.dated
.....for Rs.furnished by the
above mentioned bank and which has been fully ad-
judicated by the Collector of Stamps, in accordance
with Section 31 of the Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully,
(Licensee)

Copy forwarded toBank for Infor-
mation.

ANNEXURE III GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (here-
inafter called the Government) having agreed to
arrange for payment in (mention the appropriate
amount in foreign currency) for the import of.....
by.....(hereinafter called the 'Importer')
against the licence No.dated.....
issued under the terms and conditions of West German
Capital Goods Credit for 1983-84 and in pursuance
of import in favour of the importer against the above
mentioned agreement, we.....Bank, at the
request of the importer hereby undertake to arrange,
to deposit the amount of the disbursement made by
the.....nominated by the importer

(Name of the Commercial Bank in West Germany)
converted at the prevailing rate of exchange calculated
as per instructions issued by the Government in the
matter from time to time plus 1 per cent thereon
within 10 days of the receipt of advice of payments,
for credit to the Government account in the manner
and against the appropriate Heads of Account as indi-
cated by Government of India under the said credit
together with interest thereon at the rates of 12 per
cent per annum for the first 30 days and at 18 per
cent per annum for the period in excess thereof recko-
ned from the date of payment to the foreign supplier
or the date of reimbursement by KfW to the desig-
nated bank whichever is earlier to the date of deposit
of rupee equivalent for credit into the Government
account. The negotiable set of import documents
received from the designated commercial Bank in
West Germany will be released to the importer
after the rupee deposits contemplated above have
been made.

2. We, theBank also under-
take to indemnify and keep indemnified the Govern-
ment against any default in payment by the Importer
of any sum that may be due and payable from time
to time by the Importer to the Government at such
place and in such manner as the Government may
from time to time direct, such sums not exceeding
Rs.or any part thereof, for the time
being due and payable by the importer, together with
interest thereupon at the rate of 12 per cent per
annum for the first 30 days and at 18 per cent
per annum for the period in excess thereof reckoned
from the date of payment to the foreign supplier or
the date of reimbursement by KfW to the designated
bank whichever is earlier. The decision of the Govern-
ment as to any default in the said payment by the
importer, or on his part and in regard to the amount
payable to the Government by us.....Bank shall
be final and binding on us.....Bank.

3. WeBank further agree
that in case of increase in the value of imports or

decrease in the value of unfulfilled deliveries under
the contract as a result of change in the composite
rate of exchange, the amount of this guarantee bond
will be adjusted as on the date when the change takes
place, in proportion to this change.

4. We.....Bank further agree that the
guarantee herein contained shall remain in full force
and effect during the period that would be taken for
the performance of the said Agreement/contract and
that it shall continue to be enforceable till all the
dues to the Government under, or by virtue of this
guarantee have been fully paid and its claim satisfied
or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be
effected by any change in the constitution of the
importer or theBank and the Govern-
ment shall have the fullest liberty without affecting the
guarantee to postpone for any time and from time to
time any of the power exercisable by it against the
importer and theBank shall not be
released from its liability under this guarantee by any
exercise of the Government of the liberty with reference
to the matters aforesaid or by reasons of time being
given to the Importer or any other forbearance, act
or commission on the part of the Government or any
indulgence by the Government to the importer or by
any other matter or things whatsoever which under
the law relating to sureties shall, but for this provision,
have the effect of so releasing the
Bank from its such liability.

6. We.....Bank lastly undertake not to
revoke this guarantee during its currency, except with
previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted
to Rs.(plus interest and other charges
not expected to exceed 1 per cent of the guarantee
amount) and it will remain in force till the.....
day of* (month).....19 . Unless claims
under the guarantee are made in writing within 1½
years of this date and unless a suit or action to
enforce these claims is commenced within another
1½ years thereafter, i.e. upto . . . all Govern-
ment rights under this guarantee shall be forfeited
and we shall be relieved and discharged from all
liability thereunder.

Date theday of.....
for theBank

Accepted for and on behalf of
the President of India, by Shri.....
(Name and designation).
Signature

Signature

*8. This date shall be arrived at by adding one
month to the date upto which the Letter of Authority
is required to be kept valid Notes:—

- (1) The value of the stamped paper in which
this guarantee is to be executed is to be
adjudicated by the Collector of Stamps
under Section 31 of the Indian Stamps Act.
- (2) The value of the Bank Guarantee vide
papers 2 and 7 above shall be arrived at
after adding 1 per cent to the net C&F or
CIF value of the contract converted into
rupees at the Customs exchange rate prevail-
ing on the date of issue of the Import
Licence.

ANNEXURE IV

(Performance Bond)

Address of the beneficiary.

In consideration of your having contracted on with Messrs
 (hereinafter called the Contractor) for (Project) at a contract price of
 being a condition of the contract that a performance bond of % of the contract price be established,

we, the undersigned Bank, waiving all objections and defences under the aforesaid contract, hereby irrevocably and independently guarantee to pay to you without delay upon your first written demand any amount claimed by you up to the extent of

.....
 (in words.....)

against your written declaration that the Contractor has refused or failed to perform the aforementioned contract.

In case of any claim under this guarantee, payment will be effected to Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main (account number 50 409 100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) in favour of
 This guarantee shall expire on the (Date) by which date we must have received any claim by registered letter or by cable.

It is understood that you will return this guarantee to us on expiry of settlement of the total amount to be claimed hereunder.

Date

Ba

ANNEXURE V

Letter of Authority No.

No.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the, 198 .

(Name and address of the designated Bank)

Federal Republic of Germany

Subject:- Payment to Foreign Suppliers under Direct Payment Procedure—DM 25 Million Capital Goods Credit dated 12-9-83 from the
 Federal Republic of Germany (AL-8265832) Import Licence No. dated

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, we hereby authorise you to spend such an amount in DM as
 may be found necessary to pay

to Messrs

under the letter of credit to be opened by

for covering the import of

against contract entered into by Messrs

2. Since the amount is to be financed under DM 25 Million West German Capital Goods Credit, you may negotiate the documents upon presentation and simultaneously obtain reimbursement from Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt and pay the supplier. In case KfW is not reimbursing the amount for one reason or the other, you may approach this Department immediately for necessary reimbursement.

3. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to and a payment advice along with one set of documents (non-negotiable) sent to us for information.

4. Your banking charges under the above letter of Credit will be settled directly with you by the by remittance from India.

5. The authority will remain valid upto

Yours faithfully,

(ACCOUNTS OFFICER)

ANNEXURE V

Letter of Authority No.

No.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 198

(Name and address of the designated bank)

Federal Republic of Germany.

Subject :—Payment to Foreign Suppliers under Direct Payment Procedure—DM 25 Million Capital Goods Credit dated 12-9-83 from the Federal Republic of Germany (AL—3263832) Import Licence No. dated

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay

to Messrs

under the letter of credit to be opened by for covering the import of against contract entered into by Messrs

2. Since the amount is to be financed under DM 25 Million West German Capital Goods Credit, you may negotiate the documents upon presentation and simultaneously obtain reimbursement from Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt and pay the supplier. In case KfW is not reimbursing the amount for one reason or the other, you may approach this Department immediately for necessary reimbursement.

3. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to and a payment advice along with one set of documents (non-negotiable) sent to us for information.

4. Your banking charges under the above letter of Credit will be settled directly with you by the by remittance from India.

5. The authority will remain valid upto

Yours faithfully,

(ACCOUNTS OFFICER)

Copy to :

1. One to the Indian Bank,

2. The Importer,

3. KfW, Frankfurt in continuation of this Ministry's letter No. dt. They are requested to arrange for expeditious reimbursement immediately on request from Bank.

ANNEXURE VI

Subject : Import under West German DM 25 Million Capital Goods Credit for 1983-84—Issue of Letters of Authority for opening Letter of Credit. Import Licence No.....Dated

Dear Sirs,

With reference to letter No.dated thefrom thein which they have requested permission for opening a letter of credit through your bank under the West German DM 25 million Capital Goods Credit for 1983-84, I am to enclose the Department of Economic Affairs' Letter of Authority No.dated the

(with a spare copy)

authorising them to arrange payment upto.....to the foreign supplier. The Letter of Authority should be sent by you to the.....along with the letter of credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding.....within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10, Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date for shipments stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority, whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid import licence.

3. The.....Bank may be asked to negotiate the documents upon presentation and simultaneously obtain reimbursement from KfW and pay the supplier.

4. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the designated commercial Bank in West Germany) to effect payments in DM to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries plus 1 per cent towards incidental and Commitment charges in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of the documents from the.....The rupee equivalent of the amount disbursed to the foreign suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-1972 and 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-76 until further notice. This rate is subject to revision, if and when the IMF parity rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 12 per annum for the first 30 days and at 18 per cent annum for the period in excess thereof as mentioned in the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83, dated 10-8-83 reckoned from the date of payment to the suppliers or the date of reimbursement by KfW to the designated Bank which is earlier, and the date on which the rupee equivalent are deposited (both days inclusive) is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts, before the shipping documents are handed over to the importers.

5. These amounts should be deposited in cash either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No.233-ITC(PN)/68 dated the 24th October, 1968 as amended by Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The head of account to be credited is : "K-Deposits and Advances—B—Deposits not bearing interest-843-Civil Deposit—Deposits for Purchases etc. abroad under Direct Payment procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XV for 1983-84 DM 25 Million Credit".

6. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominating German Bank :

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice, dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the Address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

7. A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the foreign Insurance Company and/or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to KfW (Account No. 504:09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

8. The Letter of Credit may be opened in the foreign currency under which the Letter of Authority is issued.

9. Indian Agent's commission, if any, is to be paid in rupees in India.

10. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

ACCOUNTS OFFICER.

Copy forwarded to M/s.....with a copy of the Letter of Authority No.....for information, with reference to their letter quoted above.

ACCOUNTS OFFICER.

ANNEXURE VII

PROFORMA

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished ;
2. The import licence number and date and value ;
3. Number, date and amount of the guarantee furnished ;
4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance :
 - (a) Number and date of the Letter of Authority. ;
 - (b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency) ;
5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made :
 - (a) Name of suppliers ;
 - (b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier (mentioned at (a) above ;
 - (c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany ;
 - (d) Amount of rupee deposits :
 - (i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier @ 1 : 1 unit of foreign exchange = Rs.
 - (ii) Interest paid ;
 - (iii) Period for which the interest has been calculated from ;
 - (iv) Total Deposit made ;
 - (v) Date and place of deposit ;
 - (vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted ;
 - (vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi to be indicated ;
6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each Letter of Authority ;
7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed ;

(Authorised Signatures)

ANNEXURE-VIII

PROFORMA

Name of Company	Private Sector/ Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of Allocation (Rs.)	No, date and value of I.L. (Rs.)	Value of contract (foreign currency)	Value of L.C.	Amount paid against the LC (foreign currency)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note : In respect of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 Million at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs), the licensee will be required to submit in addition half yearly report as in Annexure VIII on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

ANNEXURE IX

Proforma for submission of half-year reports on progress of projects financed under West German Capital Goods Credit—
30th June/31st December

1. Name of Company and address (address of Head Office and also address of factory) ;
2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head Office is located, it should be clearly indicated) ;
3. Whether a public sector or private sector undertaking ;
4. Branch of Industry to which it belongs ;
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India ;
6. Brief Description of the project including description of the Capital Goods items of manufacture ;
7. No., date and value of the import licence ;
8. Value of supply contract(s) under the licence in DM ;
9. Amount paid to the Suppliers as on in D.M ;
10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting ;
11. Keeping of time schedule comparison of schedule with actual dates, reasons for changing the time schedule ;
12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor ;
13. Progress of the Project—
 - (i) Supply of the goods (terms of delivery)
 - (ii) Erection (kind and quality)
 - (iii) Commissioning (final acceptance, trial runs results of operation).
14. Date of completion of the Project ;
15. Economic implication of the project ;
16. Realisation of the Cost and Finance Plan comparison of plan with actual values ;
17. Any special events connected with the implementation of the project ;
18. Latest annual report of the Project Sponsor (2 copies) ;

N.B. : Strike out the portions not applicable.